जनसम्पर्क कार्यालय: एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

समाचार

ट्रांसमिशन कंपनी ने विभिन्न अति उच्चदाब उपकेन्द्रों में रूफ टाप सौर ऊर्जा पैनल लगाए – श्री बेन्डे

जबलपुर 17 दिसंबर। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध सचांलक श्री पी.ए.आर. बेन्डे ने कहा कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण हेतु अपने स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिनको सफलता भी मिली है। विगत वर्षों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप पारेषण हानि में उल्लेखनीय कमी हुई है, जो कि ऊर्जा संरक्षण की गातिविधियों का ही एक आयाम है। अति उच्चदाब उपकेंद्र में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों में सामान्य इंडिकेटिंग बल्बों की जगह एलईडी इंडीकेटिंग बल्बों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही अति उच्चदाब उपकेन्द्र में प्रकाश व्यवस्था हेतु यार्ड लाईट एवं कालोनियों में सोडियम लैम्पों के स्थान पर एलईडी का उपयोग किया जा रहा है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न अति उच्चदाब उपकेंद्रों पर रूफ टाप सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाश के लिए सामान्य बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ एलईडी बल्ब मार्च 2019 तक लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। 22 नवंबर 2018 की स्थिति में पूरे देश में 31.49 करोड़ एलईडी बल्ब लगाए जा चुके हैं जिससे प्रतिवर्ष 40,906 मिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है एवं प्रतिवर्ष 16,363 करोड़ रूपए की बचत हो रही है। साथ ही ऊर्जा की शीर्ष मांग में 8190 मेगावाट की कमी आई है तथा कार्बन डायआक्साईड के उत्सर्जन में 3,31,34,233 टन की कमी आई है। इसी प्रकार हमारे देश में 1,73,37,145 एलईडी बल्ब लगाए जा चुके हैं। ऊर्जा बचत प्रतिवर्ष 2251 मिलियन यूनिट है जिससे प्रतिवर्ष लगभग 901 करोड़ रूपये की बचत हो रही हैं। प्रदेश की शीर्ष मांग में 451 मेगावाट कमी के साथ 18,23,734 टन कार्बन डायआक्साईड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष कम हुआ है। इसी प्रकार एलईडी ट्यूबलाईट सामान्य ट्यूबलाईट की जगह लगाए जा रहे हैं। ऊर्जा सरंक्षण में वृद्धि, ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवकरणीय स्त्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के द्वारा ऊर्जा मामले में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बना जा सकता है, तथा वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है।

श्री बेन्डे ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां विद्युतीकरण संभव नहीं हो सका है, वहां केन्द्र शासन द्वारा विद्यार्थियों को 70 लाख सोलर स्टडी लैंप दिए जा रहे हैं। हमारा देश नवकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में सोलर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के हिसाब से विश्व में 5वें तथा 6वें पायदान पर पहुंच चुका है। शासन द्वारा कुसुम योजना (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) के अंतर्गत 27.5 लाख सोलर पंप लगाए जाने की योजना बनाई जा रही है। हमारे प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सोलर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य 20 गीगावाट से बढ़ाकर 40 गीगावाट कर दिया गया है। अभी तक 21 राज्यों में कुल 26 गीगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी हैं। सबसे बड़ा सोलर पार्क 2 गीगावाट क्षमता का कर्नाटक के पावागडा में स्थापित किया जा रहा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रदेश मे भी सोलर ऊर्जा का कार्य प्रगति पर है एवं वर्तमान में सोलर ऊर्जा की स्थापित क्षमता (रम्स रीवा सहित) 1530 मेगावाट हो गई है। भारत सरकार द्वारा 3 लाख सोलर सड़क

बत्ती, जहां पर विद्युतीकरण संभव नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में लगाई जा रही है। इसी प्रकार 25 केडब्ल्यू पीक क्षमता के सोलर पावर प्लांट विभिन्न संस्थानों को विद्युत प्रदाय करने हेतु लगाए जाने की योजना है। सोलर ऊर्जा का वृहद् स्तर पर उपयोग में लाने के लिये इंटरनेशनल सोलर एलाइंस का गठन किया जा चुका है, जिसका मुख्यालय भरत में स्थापित होगा। भारत सरकार द्वारा 60 शहरों को सोलर ऊर्जा शहर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें से अभी तक 48 शहरों को विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जा चुकी है। इन शहरों में हमारे प्रदेश के भी 4 शहर क्रमश: ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा सम्मिलित है।

समाचार क्रमांक 488/2018

(राकेश पाठक)
वरिष्ठ जनसम्पर्क अधिकारी